[श्री दिगम्बर सिंह]

कमी उत्तर प्रदेश और मथुरा जिले में है । इसका एकमात्र हल यह है कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था स्वयं करे । यदि शीघ्र बिजली की समस्या हल नहीं की जाती तो उससे रबी की फसल के उत्पादन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा । जितने समय देने की घोषणा की जाती है उसकी चौथाई समय भी नहीं मिलता । तेल शोधक कारखाने, मथुरा में जितना बिजली उत्पादन की क्षमता है उतनी कारखाने को आवश्यकता नहीं । कारखाने के अतिरिक्त बिजली को माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले और नगर को दे दें। तो उससे सिंचाई को बिजली अधिक मिल जायेगी और मथुरा नगर जो अव्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश का सबसे गन्दा नगर है, और रात के अंधेरे में जनता और देश और विदेश से आये यात्री गन्दगी से परेशान होते हैं और बिजली के बिना नल न चलने से प्यासे मरते हैं उनको भी सुविधा होगी ।

माननीय ऊर्जा मंत्री दिवाली पर कारखाने की बची हुई बिजली लेकर कृष्ण भगवान की जन्म स्थली और बृजवासियों को कम से कम दिवाली पर अंधेरे से बचाने की कृपा करें और बड़ी कृपा हो यदि पवित्र नगरी की गन्दगी और अंधेरे को भी आ कर देख लें ।

(vi) NEED FOR REMOVAL OF ANOMALY BETWEEN B.A. (MATHS) AND B.Sc. (MATHS.) IN REGARD TO APPOINTMENTS IN KENDRIYA VIDYALAYAS.

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): Sir, in the Directorate of Education, Delhi, for appointment to the Grade o. T.G.T. in the group of Science A, only B.Sc. (with Chemistry, Physics and Mathematics) are eligible whereas the candidates with the qualification of B.A. (maths) are not considered eligible. While on the one hand, there is an acute shortage of mathematics teachers in the Directorate of Education, on the other, B.A. (Maths) candidates are rotting both in the Employment Exchange and M.C. Primary Schools, Delhi, for the last several years. Moreover, B.Sc. candidates are hardly available at present to meet the full demand of the Directorate of Education.

It is quite strange that in the Kindriya Vidyalayas, in all the aided schools in Delhi and also in all the Government Schools in various States like Punjab, Haryana, U.P. and Himachal Pradesh, B.A. (Maths) candidates are invariably considered eligible for the post of T.G.T. (Maths). Keeping in view the shortage of mathematics teachers in the Directorate of Education, I urge upon the Minister of Education and Culture to look into the matter and remove this anomaly by making all such B.A. (Maths) candidates eligible for appointment as mathematics teachers in the Directorate of Education. By doing so a great number of candidates registered in the Employment Exchange, Delhi as well as Assistant teachers in M. C. Primary Schools, Delhi would be benefited.

(vii) NEED TO STOP IMPORT OF SYNTHETIC YARN AND TO PROMOTE EXPORT OF COTTON

श्री मनफूल सिंह चौधरी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में सिन्थेटिक यार्न बाहर के देशों से बड़ी भारी तादाद में आ रहा है और कपड़ा मिलों वाले आज जो कपड़ा बना रहे हैं, उसमें 80 प्रतिशत सिन्थेटिक यार्न और 20 प्रतिशत कोटन यार्न इस्तेमाल कर रहे हैं ।

हमारे देश में जो कोटन पैदा हो रही है, वह भी बड़ी भारी तादाद में हो रही है और इस देशी कोटन और नरमे को खपत का स्थान सिन्थेटिक यार्न ने ले लिया है और एक्सपोर्ट हमारी कोटन का नहीं के बराबर हो रहा है । इस सबका नतीजा यह हो रहा है कि कोटन का भाव दिन पर दिन गिरता जा रहा है ।

कोटन के उत्पादन में जो खर्चा इस मंहगाई के जमाने में हो रहा है, उसका उचित मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है,

वह बहुत कम है। जो सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है, उससे ज्यादा तो एक क्विंटल पर किसान का खर्च होता है।

प्रश्न यह कि प्रथम तो सिन्थैटिक यार्न का आयात बन्द होना चाहिये, दूसरे हमारे देश का कपड़ा हमारे देश के मिलों में प्योर कोटन का बनाया जाना चाहिये और अगर सिन्थैटिक यार्न का कपड़ा हमारे देश के मिलों में बने तो कोटन का एक्सपोर्ट खुले रूप में होना चाहिये ताकि किसान की कोटन का मूल्य बढ़ सके और किसान का घर पूरा हो सके।

मगर आज जो सिन्थैटिक यार्न का आयात किया जा रहा है और कोटन का निर्यात बन्द किया जा रहा है, यह किसान विरोधी है और मिल मालिकों के साथ भारी पक्षपात है। यह नीति कृषि प्रधान देश में अपनाई जानी उचित नहीं है। अतः केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि किसान को लाभ पहुंचाने और कोटन उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिये कोटन का निर्यात खुले रूप से किया जाना चाहिये और कोटन बाहर से मंगाई जाने में पूरी तरह से रोक लगाई जाय, जैसे गत वर्ष पाकिस्तान से मंगाई गई थी, और दूसरे सिन्टिथैक यार्न के आयात पर भी पाबन्दी लगाई जानी चाहिये।

(viii) IMPENDING STRIKE BY TEXTILE WORKERS OF TAMIL NADU AND PONDICHERRY.

SHRI ERA MOHAN (Coimbatore): All the textile unions of Tamil Nadu and Pondicherry have given a joint call for indefinite strike from 11-11-82 onwards in all the 130-odd mills involving more than 2 lakh workers. In Coimbatore city alone there are 103 textile mills employing more than 1 lakh workers. The textile workers were getting so far higher bonus than the statutory minimum of 8.33 per cent under the S.I.M.A. formula arrived at unanimously between the managements and all trade unions. Now, under communication F. No. 204/21/80-II A. II dated 4-12-80, the Central Board of Direct Taxes has declared that any amount paid as bonus in excess of 8.33 per cent statutory minimum is subjected to income-tax. This has become a convenient handle for the managements to declare only the statutory minimum bonus of 8.33 per cent.

If the textile workers of Tamil Nadu and Pondicherry are not prevented from going on strike, from 11-11-82, there will definitely be serious loss in production which may not be able to be recovered even in a decade.

The textile workers of Tamil Nadu and Pondicherry must be enabled to get bonus under S.I.M.A. formula which is an improvement over the Bonus Act, Formula by directing the Central Board of Direct Taxes to rescind the order in question and all the profit-making organisations should not be subjected to income-tax for paying higher bonus than 8.33 per cent.

(ix) RESERVATION FACILITY AT PATNA JUNCTION.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, पटना बिहार की राजधानी है। वहां से प्रत्येक दिन हजारों यात्री राज्य और देश के सुदूर स्थानों तक यात्रा करते हैं। यात्रियों को सुविधा के लिये वर्षों से पटना जंक्शन पर आरक्षण की व्यवस्था है। इसके लिये वहां बाजाप्ता कार्यालय खुला हुआ है। सभी गाड़ियों में आरक्षण के लिये वहां भीड़ लगी रहती है। भारी भीड़ को देखते हुये वहां आरक्षण की सुविधा और बढ़ाने की आवश्यकता है। परन्तु आश्चर्य की बात है कि रेलवे प्रशासन वहां से दैनिक आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पटना जंक्शन की स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय हो जायेगी।